

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक-डी0डी0-1-विविध-111 / 39 / 2022-23 (पार्ट-V).....

पटना, दिनांक-.....

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सभी भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

विषय:- न्यायिक आधारभूत संरचना विकास के निमित्त केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत ली गई योजनाओं के अनुश्रवण के संबंध में।

प्रसंग:- सरकार के विशेष सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-5499 / जे0, पटना, दिनांक-25.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से न्यायिक आधारभूत संरचना विकास के निमित्त केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति एवं निधि के व्यय से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है।

अतः संलग्न विहित प्रपत्र (कॉलम-6 को छोड़कर) में एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

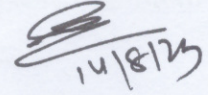
(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 6580 (ग) 15/8/23

दिनांक-16/8/23

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

विशेष सचिव

पत्र संख्या-जा0/या0-31-56/2023.5499.../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

3065 ITM 3
21/7/23

ई-मेल
अत्यावश्यक

होर्क में

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

पटना, दिनांक 25-7-23

विषय :- न्यायिक आधारभूत संरचना विकास के निमित्त केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत ली गई योजनाओं के अनुश्रवण के संबंध में।

प्रसंग:- अवर सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय(न्याय विभाग), भारत सरकार का पत्र संत्र-J-11017/07/2023-JR (e-file 8353) दिनांक-14.07.2023 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत शुरू की गई योजनाओं की प्रगति की गति एवं निधि के उपयोग के अनुश्रवण के निमित्त विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा योजनाओं की प्रगति एवं निधि के व्यय संबंधी याचित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन,

(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

DD-1/24/2023
31-7-23
ज्ञापांक 5499/जे0 पटना, दिनांक 25-7-23

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 5499/जे0 पटना, दिनांक 25-7-23

प्रतिलिपि:- उप सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 5499/जे0 पटना, दिनांक 25-7-23

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24-7-2023

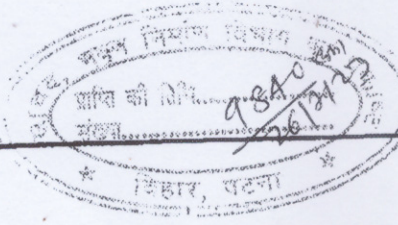
(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

24-7-23

PADram DrakshiGul Sapli Yn dno

28/07/23

984033



Time
2387-30
9/7/23

DD-1/24/2023

File No. J-11017/07/2023-JR (e-file 8353)

Government of India
Ministry of Law & Justice
Department of Justice

26, Mansingh Road, Jaisalmer House.
New Delhi-110011, 14th July, 2023

To

The Law/Home Secretary,
All State Governments and UT Administrations

Sub: Monitoring of Projects taken up under CSS on Judicial Infrastructure (9174) -
regarding

Sir/Madam,

In the VC meeting held from 26-30 June 2023, all the State Governments /UTs were requested to utilize the unspent balance available with them at the earliest. It is felt that commensurate with utilization of funds, pace of progress of the agency-wise projects, taken up under the above scheme, also needs to be monitored, for their time-bound completion.

2. Accordingly, it has been decided to compile data in the following format:

Sl. No.	Name of Agency executing the work	Project name With location	Total Project Cost	Funds allocated for the project	Funds approved and limit set by SSM	Fund utilized by Agency	Funds remaining to be spent	Date of Completion of the project	Physical status of the project	Deadline for utilization by Agency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3. All the States/UTs are requested to provide the requisite information, duly filled in the above format, at the earliest.

4. This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

(Amarjeet Sroa)

Under Secretary to the Government of India
Tele No. : 011-23072140

Copy for necessary action to:

1. Finance Secretary, All States/UTs
2. Registrar General, all High Court
3. PWD secretary, all States/UTs.
4. A copy to be placed in concerned file (File No. J-11017-04/2023-JR (e-file 8279))

Copy for information to: PPS to Secretary (J), PPS to JS (NMJR), PS to Dir (NMJR)